



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

गई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20, 1968 (चैत्र 31, 1890)

No. 16]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20, 1968 (CHAITRA 31, 1890)

इस भाग में चित्र पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह असत्र संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 1 अप्रैल 1968 तक प्रकाशित किये गये हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 1st April 1968:—

बंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
51	No. 46 ITC(PN)/68, dt. 25-3-68.	Ministry of Commerce	Imports from the U.S. AID commodity Programme Assistance 1966 (Aid Loan No. 386-H- 160).
52	No. 47-ITC(PN)/68, dt. 27-3-68.	Do.	Imports from U.S.A. under U.S. Aid loans.
53	No. 11(1)/Tar/67, dt. 28-3-68.	Do.	Reduction of duty of customs leviable on silk raw (excluding silk waste, ncils and silk Ccccs).
	संख्या 11(1)-टैरिक/67 दिनांक 28 मार्च 1968।	वाणिज्य मंत्रालय	कार्यक्रम रेशम पर (रेशम व्यर्थ गटिलयों तथा रेशम के कोयों को छोड़ कर) आरोप्य सीमा-शुल्क की कटौती।
54	No. 48-ITC(PN)/68, dt. 29-3-68.	Min. of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the year April 1967—March 1968.
55	No. RS/1/1/68-L, dt. 30-3-68.	Rajya Sabha Secretariat	President progress the Rajya Sabha.
	संख्या आर० एस० 1/1/68 दिनांक 30 मार्च 1968।	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का समावसान।
56	No. 19(1)/63-EAC, dt. 30-3-68.	Ministry of Commerce	Exports Houses.
	संख्या 19(1)/63-ई० ए० सी० दिनांक 30 मार्च 1968।	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात सदन
57	No. 49-ITC(PN)/68, dt. 1-4-68.	Min. of Commerce	Import of Machine Tools—Particulars to be furnished by importers.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these *Gazettes*.

विषय सूची (CONTENTS)

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—बंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर
नियमों, विनियमों तथा आदेशों और
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

303

भाग I—बंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)
भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

411

पृष्ठ	पृष्ठ	
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिक नियम और आदेश	197
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ-लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	315
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसे	143
भाग II—खंड 2—विवेयक और विवेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	51
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	139
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसे	71
825	पूरक संख्या 15—	
	13 अप्रैल 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	621
	23 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के द्विरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आँकड़े	635

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page
	303.
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	411
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	319
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (1)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministries of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	825

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	Page
	1841
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	197
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Sub-ordinate Offices of the Government of India	315
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	143
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	51
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	139
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	71
SUPPLEMENT No. 15—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th April 1968	621
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 23rd March 1968	635

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(राष्ट्र मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकायों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1968

सं 27-प्रेज/68—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री महेश दत्त शर्मा,
सहायक पुलिस अधीक्षक,
जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।

श्री सुभाष चन्द,
हैड कान्स्टेबल सं 74,
'ई' कम्पनी, 15वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्र दल,
करहल, जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21 अप्रैल, 1966 को श्री महेश दत्त शर्मा, एस 310 ओ० (पुलिस), शिवपुर द्वारा सरारी एवं गोत्रा आमों के नजदीक धने जंगल में डाकू राम निवास बाबा के गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए एक छापे का आयोजन किया गया। पुलिस दल को दो भागों में बांटा गया, एक दल रोकने के लिए तथा दूसरा छाड़ेँने के लिए। इनमें से एक भाग का नेतृत्व स्वयं श्री महेश दत्त शर्मा कर रहे थे तथा दूसरे का हैड कान्स्टेबल सुभाष चन्द। दोनों भागों ने डाकुओं को घेरे में लेने के लिए दो ओर से बढ़ना मुरू किया। डाकुओं ने जो 303 राईफलों एवं स्वचालित पिस्तोलों से लैस थे, दोनों दलों के बीच खाली स्थान से बच निकलने के प्रयास में पुलिस दल पर जिसका नेतृत्व श्री सुभाष चन्द कर रहे थे, गोलीबारी शुरू कर दी। डाकुओं द्वारा भारी गोलीबारी के बावजूद, श्री सुभाष चन्द ने अपने दल को लेकर रोकने वाले दल की ओर बढ़ना जारी रखा। श्री महेश दत्त शर्मा दूसरे दल के डाकुओं के कब्जे में आ जाने के खतरे को देखते हुए, उनकी सहायता के लिए एक छोटे पुलिस दल के साथ शीघ्र बढ़े। ऐसा करते हुए श्री शर्मा ने स्वयं को बहुत भारी खतरे में डाल दिया। डाकुओं द्वारा भारी एवं बराबर गोलीबारी की परवाह न कर श्री शर्मा ने आगे बढ़ना जारी रखा जबतक कि उनके दल ने हैड कान्स्टेबल सुभाष चन्द के दल से सम्पर्क स्थापित न कर सकिया। तब दोनों पुलिस दलों ने डाकू गिरोह पर संयुक्त धावा बोला और डाकू मुखिया राम निवास बाबा तथा गिरोह के दो सदस्यों को गोली से उड़ा दिया।

इस कार्यवाही में श्री महेश दत्त शर्मा और हैड कान्स्टेबल सुभाष चन्द दोनों ने ही उच्च कोटीय कर्तव्य-परायणता, पहल-शक्ति एवं विशिष्ट साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द को विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 अप्रैल, 1966 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा सीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1968

प्रस्ताव

सं 27/5/67-समन्वय—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रस्ताव सं 27/22/63-समन्वय, दिनांक 29 फरवरी 1964, के अधीन गठित सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया है:—

(I) अध्यक्ष—उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री

(II) छ: पदेन सदस्य:—

(क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ का अध्यक्ष;

(ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर का उपाध्यक्ष;

(ग) वाणिज्य तथा उद्योग के एसोसिएटड चैम्बर का अध्यक्ष;

(घ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय निर्माता संगठन;

(ङ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयातकर्ता संगठन;

(च) अध्यक्ष, अखिल भारतीय नियांतकर्ता;

(III) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद सदस्य जिनकी संख्या सात से कम नहीं होगी;

(IV) सचिव, वित्त मंत्रालय;

(V) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड;

(VI) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक, राजस्व विभाग;

(VII) सदस्य (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड का एक सचिव परिषद् के सचिव का काम करेगा।

2. परिषद् का अध्यक्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को परिषद् की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित कर सकता है।

आवेदन

आवेदन दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

धर्म प्रकाश आनन्द, अतिरिक्त सचिव

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1968

संकल्प

सं. कोयला 2-8(7)/67—भारत सरकार के इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग) के विनाक 31 जनवरी, 1968 के संकल्प संख्या-कोयला 2-8(7)/67 की अनुवृत्ति में यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास नगम समिति की अन्तिम रिपोर्ट दिये जाने की अवधि को और दो महीने बढ़ा दिया जाय। तदनुसार समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 30 जून, 1968 को देगी त कि 30 अप्रैल, 1968 को, जैसा कि पहले घोषित किया गया था।

आवेदन

आवेदन दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th April 1968

No. 27-Pres./68.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police.

Names of the officers and ranks

Shri Mahesh Dutt Sharma,
Assistant Superintendent of Police,
District Morena, Madhya Pradesh.

Shri Subhash Chand,
Head Constable No. 74,
'E' Company, 15th Battalion,
Special Armed Force,
Karhal, District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 21st April, 1966 a raid was organised by Shri Mahesh Dutt Sharma, S.D.O. (Police) Sheopur to arrest the gang of dacoit Ram Niwas Baba in the thick jungle near the villages of Sarari and Gotra. The Police party was divided into two groups, one as a stop party and the other as a driving party. One of these groups was led by Shri Mahesh Dutt Sharma himself and the other by Head Constable Subhash Chand. The two groups started closing on the gang of dacoits from two sides. The dacoits who were armed with .303 rifles and automatic pistols opened fire on the police party led by Shri Subhash Chand in a bid to escape through the gap between the two parties. Despite heavy fire by the dacoits, Shri Subhash Chand continued to lead his group towards the stop party. Shri Mahesh Dutt Sharma noticing that the other Police party was in danger of being over-

सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों, प्रबन्ध निवेशक, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सभी निवेशकों को भेज दी जाय।

यह भी आवेदन दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाय।

एस० एस० के० रामस्वामी, उप-सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, विनाक 23 मार्च 1968

सं० एफ० 8-1/68-वा०१० एस० ४—शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल के नामन से संबंधित शिक्षा मंत्रालय की तारीख 23 नवम्बर, 1967 की समसंचयक अधिसूचना के सिलसिले में

मेजर के० सी० पाल्टे,
सहायक निदेशक,
(कैडेट कोर्स और कालिजेज)
हरियाणा राज्य,
चन्दीगढ़।

को मुर्त अभी से तारीख 27 अगस्त, 1968 तक के लिये श्री आर० एस० सूद के स्थान पर शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केन्द्रीय सलाहकार मंडल का सदस्य नामित किया गया है।

आर० एल० आनन्द, अवर सचिव

powered by the dacoits, rushed with a small police party to their help. In doing so, Shri Sharma exposed himself to a very grave risk. Undeterred by heavy and continuous firing by the dacoits he continued to advance till his party established contact with the party of Head Constable Subhash Chand. The two Police parties then launched a combined offensive on the dacoit gang, and shot dead the dacoit leader Ram Niwas Baba and two members of his gang.

In this action, both Shri Mahesh Dutt Sharma and Head Constable Subhash Chand exhibited a high sense of duty, initiative and conspicuous courage.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and in the case of Shri Subhash Chand the award carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st April 1966.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President.

LOK SABHA SECRETARIAT

(P. U. Branch)

New Delhi-1, the 1st April 1968

No. 4(2)-PU/68.—In partial modification of Notification No. 4(2)-PU/67, dated April 7, 1967, and in pursuance of the Motion adopted by the Lok Sabha on the 20th March, 1968 and the Motion adopted by the Rajya Sabha on the 26th March, 1968, the term of office of Members of the Committee on Public Undertakings, except that of Shri Vimalkumar M. Chordia, M.P., who retires from the Rajya Sabha on the 2nd April, 1968, has been extended up to the 30th April, 1968.

A. L. RAI, Dy. Secy.

New Delhi-1, the 4th April 1968

No. 3/1/68/PAC.—In pursuance of the motions adopted by the Lok Sabha on the 20th March, 1968 and the Rajya Sabha on the 26th March, 1968, the term of office of the following members of the Committee on Public Accounts (1967-68) has been extended upto the 30th April, 1968 :

Chairman

1. Shri M. R. Masani,

Members

2. Shri Syed Ahmed Aga.
3. Shri C. K. Bhattacharyya.
4. Sardar Buta Singh.
5. Shri Shivajirao S. Deshmukh.
6. Shri R. Muthu Gounder.
7. Shri D. K. Kunte.
8. Shri N. R. Laskar.
9. Shri V. Viswanatha Menon.
10. Shri K. K. Nayak.
11. Shri Narendra Kumar Salve.
12. Shri Yogendra Sharma.
13. Shri Sheo Narain.
14. Shrimati Tarkeshwari Sinha.
15. Shri P. Viswambharan.
16. Shri Om Mehta.
17. Shri B. K. P. Sinha.

AVTAR SINGH RIKHY, Dy. Secy.

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th April 1968

SUBJECT : Long Vacation, 1968

No. F. 44/68-S.C.A.(G).—In pursuance of Rule 4, of Order II, of the Supreme Court Rules, 1966 the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday the 6th May 1968 to Sunday, the 14th July, 1968 (Both days inclusive) and will re-open on Monday, the 15th July 1968.

The Hon'ble the Chief Justice of India has also been pleased under Rule 6, Order II of the aforesaid Rules, to appoint the Hon'ble Mr. Justice K. S. Hegde and the Hon'ble Mr. Justice A. N. Grover to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under these Rules may be heard by a Judge sitting singly, for the respective period shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice A. N. Grover from 6th May to 9th June 1968 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice K. S. Hegde from 10th June to 14th July 1968 (both days inclusive).

The Hon'ble Mr. Justice A. N. Grover will sit on Tuesdays the 21st May and 4th June 1968. The Hon'ble Mr. Justice K. S. Hegde will sit on Tuesdays, the 18th June and 2nd July 1968. Sittings will, however, continue on the next succeeding days if matters fixed for any day, are not finished on that day.

Except on Saturdays and holidays, the office of the Court shall be open during vacation between 8 a.m. to 12.30 p.m. daily; but on the days notified for the vacation sittings the hours shall be 10 a.m. to 4.30 p.m.

No plaints, appeals, petitions or other documents, except those which require to be immediately or promptly dealt with will be filed or received in the Registry of the Court during the period the Court is in Vacation.

The Registry will open for filing purposes from Monday, the 15th July 1968, but as from the 8th July, 1968, for convenience of parties, the office of the Court will receive during the working hours all plaints, appeals, petitions, or other documents which may be ready for filing with the parties.

Y. D. DESAI, Registrar

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue and Insurance)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April 1968

No. 27/5/67-Coord.—The Customs and Central Excise Advisory Council, as constituted under the Ministry of Finance (Department of Revenue) Resolution No. 27/22/63-Coord., dated the 29th February, 1964 is reconstituted as under :—

- (i) Chairman—Deputy Prime Minister & Minister of Finance.
- (ii) Six *ex-officio* Members :—
 - (a) The President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry;
 - (b) Vice-President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry;
 - (c) The President of the Associated Chambers of Commerce & Industry;
 - (d) President, All India Manufacturers' Organisation;
 - (e) President, All India Importers' Organisation;
 - (f) President, All India Exporters' Association.
- (iii) Not less than seven Members to be nominated by the Government of India from time to time;
- (iv) Secretary, Ministry of Finance;
- (v) Chairman, Central Board of Excise & Customs;
- (vi) Gold Control Administrator, Department of Revenue;
- (vii) Member (Customs), Central Board of Excise & Customs;
- (viii) Members (Central Excise), Central Board of Excise & Customs.

One of the Secretaries to the Central Board of Excise & Customs will act as Secretary of the Council.

2. The Chairman of the Council may specially invite any other person or persons to attend any meeting of the Council.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. R. ANAND, Additional Secy.

MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS

Department of Mines & Metals

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April 1968

No. C2-8(7)/67.—In continuation of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) Resolution No. C2-8(7)/67 dated 31st January, 1968, it has been decided to extend by another two months the period for submission of the final Report of the National Coal Development Corporation Committee. The Committee will accordingly present its final report to the Government by 30th June, 1968 instead of 30th April, 1968 as announced earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all Ministries of the Government of India, President Secretariat, Cabinet Secretariat, P.M.'s Secretariat, Planning Commission, C & A.G. of India, A.G. Commerce, Works and Miscellaneous, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats, Managing Director, National Coal Development Corporation Ltd., Ranchi and All Directors of N.C.D.C.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. K. RAMASWAMI, Dy. Secy.

(Department of Iron & Steel)

New Delhi, the 8th April 1968

No. SC(I)-2(27)/65-III.—The Government of India have decided to constitute a Steel Saving Board under the Ministry of Steel, Mines & Metals (Department of Iron and Steel) to advise on measures for effecting economy in the use of steel.

The composition of the Board will be as follows:—

1. Secretary, Department of Iron & Steel.	<i>Chairman</i>
2. General Manager, Rourkela Steel Plant, Rourkela, Orissa.	
3. General Manager, Durgapur Steel Plant, Durgapur, West Bengal.	
4. General Manager, Bhilai Steel Plant, Bhilai, Madhya Pradesh.	
5. General Manager, Tata Iron & Steel Company Limited, Jamshedpur.	
6. General Manager, Indian Iron & Steel Company Limited, Burnpur, West Bengal.	
7. Chief Engineer, Central Engineering and Design Bureau, Hindustan Steel Limited, Ranchi.	
8. Director, Indian Standards Institution, New Delhi.	
9. Chairman, Institution of Engineers (India), New Delhi.	
10. President, Indian Institute of Welding, Calcutta.	
11. A representative of Ministry of Defence Production, New Delhi.	
12. A Representative of Ministry of Industrial Development and Company Affairs, (Department of Industrial Development), New Delhi.	
13. A Representative of Ministry of Works, Housing and Supply, New Delhi.	
14. A Representative of Planning Commission, New Delhi.	
15. Director General of Technical Development, New Delhi.	
16. Director, Central Mechanical & Engineering Research Institute, Durgapur.	
17. Director, Structural Engineering Research Centre, Roorkee.	
18. Iron and Steel Controller, Calcutta.	
19. President, Indian Institute of Architects, Bombay.	
20. Shri C. N. Kapur, Joint Director, (Iron & Steel), Office of the Iron & Steel Controller, Calcutta will act as Secretary of the Board.	

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 19th January 1968

No. EL.II.1(7)/65.—With a view to establishing closer relations between suppliers and users of electricity and

affording opportunities for consultation relating to the various aspects of power development in the country, such as generation, transmission and distribution, and also the services provided by the electricity undertakings, the Government of India have decided to set up a Central Electricity Consultative Council.

2. The composition of the Council will be as under:—

Chairman

(1) Union Minister for Irrigation and Power.

Members

(2) Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power.

(3) Five Ministers from State and/ or Union Territories.

(4) Five Chairman of State Electricity Boards.

(5) Fifteen Members of Parliament.

(6) Secretary, Ministry of Irrigation and Power.

(7) Representatives of the Ministries of the Government of India,

(a) Ministry of Railways (Railway Board).

(b) Ministry of Steel, Mines and Metals.

(i) Department of Iron & Steel.

(ii) Department of Mines and Metals.

(c) Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Department of Agriculture).

(d) Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development).

(e) Ministry of Finance (Department of Expenditure).

(8) Representatives of—

(a) The Planning Commission.

(b) The Heavy Electricals, Bhopal.

(c) The Bharat Heavy Electricals Ltd.

(9) Vice-Chairman, Central Water and Power Commission.

(10) President, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry or his representative.

(11) A Representative of the Federation of Electricity Undertakings of India.

(12) Chairman, Indian Electrical Manufacturers Association or his representative.

Member-Secretary

(13) Director (FE & P), Ministry of Irrigation & Power.

Chairman may invite any other person to attend the meetings of the Council as he may consider necessary.

3. In order to ensure fairly rapid rotation, the tenure of the Council may be for two years at a time.

4. (a) The Council will consider and make recommendations on the following subjects:—

(i) Matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings as may be referred to it for consideration, by the Union Minister for Irrigation and Power.

(ii) Other matters relating to the generation, supply and distribution of electricity and the services and facilities provided by the electricity undertakings which individual Members of the Council may, with the approval of the Chairman, desire to be included in agenda.

(iii) Any other matter of general public interest or public convenience relating to supply and distribution of power.

(b) The Council will be purely consultative in character.

(c) Question relating to staff, discipline and appointments shall not be brought before the council.

5. (a) The Council will meet at least once a year.

(b) The Chairman may constitute committees or sub-committees of the Council to advise the Government on specific problems relating to the services and facilities provided by the electricity undertakings.

(c) Any member wanting to bring up a subject for discussion should give a clear notice of one month to the Secretary and state briefly the subjects to be discussed. The Secretary will circulate the agenda giving the members at least 10 days' notice together, as far as possible, with memorandum on each item. Urgent business may, however, be brought forward for consideration without notice but with the approval of the Chairman. The Chairman may rule out a subject at his discretion.

(d) The proceedings of the meetings of the Council will be confidential, but a short summary of the proceedings will be ordinarily prepared and given to the press.

6. The members of the Council will draw travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Council at the rates fixed by the Government from time to time.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the members concerned, the State Governments, the State Electricity Boards, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

